RESEARCH FRONT

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

भारतीय प्रजातांत्रीक चुनाव तथा कृषि मजदूरो की समस्या : एक अम्बेडकरवादी दृष्टिकोन

नितिन वसंतराव खोब्रागडे, एम.ए. राज्यशास्त्र, विद्याभारती महाविद्यालय, अमरावती-४४४६०२ (महाराष्ट्र)
nv_khobragade@rediffmail.com

विश्व समुदायमें, भारत को विकासशील राष्ट्र की संज्ञा दि जाती है | यद्यापि भारत राष्ट्र को अंग्रेजी साम्राज्यवादी दासता का त्याग कर ७० साल बीत चूके है फिर भी यहाँ मजदूरो के आर्थिक विकास की समस्या भयंकर स्वरुप से व्याप्त है, भारत के संविधान निर्माता सभाने नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षीतता देने में जागृकता दिखाई तथा संविधान के एक स्वतंत्र भाग १५ को निर्वाचन से सबंध्द किया| इस भाग के अनूच्छेद ३२४ से लेकर ३२९ तक निर्वाचन के सबंध में विस्तृत उपबंध किये गये है [१].

स्वतंत्र भारत के संविधान शिल्पी डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय, कृषी मजदूरो के आर्थिक विकास में सकारात्मक परिवर्तन हेतू 'State and Minorities' लेख II के अंतर्गत भारतीय आर्थिक संरचना की विस्तृत रुपरेखा विकसित की है, जिसमें मुख्यत: प्रथमता सभी आधारभूत उद्योगो को राज्य स्वाधीन करके स्वयं या स्थापित लोगनिगमों द्वारा चलाने की; द्वितिय राष्ट्रीयकृत विमा तथा प्रत्येक प्रौढ नागरिकों का अनिवार्य जीवन बीमा निकालने की तथा तृतीय कृषी को राज्यउद्योग घोषीत करने की पहल की है| जिसके अनुसार डॉ.अम्बेडकर संवैधानिक कानून द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था लाने के हिमयाती रहे[२]| स्पष्ट है कि वे आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को अनिवार्य मानते थे | भारतीय कृषी मजदुरों की समस्या समाधान भी उपरोक्त सिध्दांत में खोजा जा सकता है. राज्य समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 'प्रथमता समाज के निम्नतम स्तर की माँग के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख उद्योगों एंव कृषि योग्य भूमि का राज्यस्वामित्व; द्वितिय राज्यद्वारा उत्पादन साधनों की देखभाल; तथा तृतीय जाति, वंश, वर्ग आदी भेदभाव रहित समाज में उत्पादन का न्यायपूर्ण वितरण[३]| अर्थव्यवस्था को मौलिकता प्रदान की जाती हैं. अर्थात सन्तुलित आर्थिक विकास हेतू स्वतंत्र भारतिय संविधान की उद्देशपत्रिका में अर्न्तभूत समानता, स्वतंत्रता एंव बंधूभाव पर आधारीत जाति-वंश-वर्गविहीत आदर्श समाज व्यवस्था की | डॉ अम्बेडकरने वकालत की थी तथा वर्ग विहित समाज को ही आर्थिक लोकतंत्र की सज्ञां दि थी[४]| वे आर्थिक-सामाजिक, लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र से अग्रगामी मानते थे | प्रत्येक व्यक्ती हेतू व्यवसाय की स्वतंत्रता, श्रम का उचित मोबदला तथा वेतन में समानता ही इसकी प्रमुख माँग रही है | कृषी मजदूरों की समस्या का समाधान उपरोक्त तथ्यों मे दिखाई पडता है. यह सत्य प्रतित होता है की, कृषि मजदूरों की समस्याओं का उच्चाटन 'मानवी मूल्य तथा आर्थिक कल्याण' पर ही संभव है-[५]|

समसामायिक राजकिय परिवेश, जुलाई १९९१ से भारत में उदारीकरण, खाजगीकरण एंवम् जागतिकीकरण पर आधारीत व्यापक आर्थिक नीती व सुधार को अपनाया | भारत द्वारा गॅट (GATT) समझोते पर हस्ताक्षर किये गए तथा अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार संगठन (WTO) का भी सदस्य बन गया है | समसामायिक आर्थिक सुधार की प्रमुख विशेषताए अंग्राकींत रुप से है. औद्योगिक लायसन्स नीती का उदारीकरण, उद्योगोपर स्थान संबंधी मर्यादा का अभाव एकाधिकार एंव व्यापार व्यवहार कानून के अंतर्गत एकाधिकार संबंध की तरतुदीयो को रद्द करना; विदेश विनिमय नियंत्रण कानून का उच्चाटन, देशांतर्गत उद्योग में बहूराष्ट्रीय कम्पनीया; परकीय पूंजी एंव तंत्रज्ञान को अधिक मुक्त प्रवेश; निर्यात आधारित उद्योगो में शतप्रतिशत पूंजी निवेश को परवानगी; उद्योगो के विकास हेतू निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका; आयात महसूल में बड़े पैमाने पर कपात तथा आयात संबंधी बंधनों का उच्चाटन जिसके कारण स्वयं देशी उद्योगो को उनसे प्रतिस्पर्धा करने को बाध्य किया| सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के निगुंतवणूक की प्रक्रिया द्वारा निजीकरण तथा कुछ उद्योगो की निजीकरणो में बिक्री; देशी बीमा, उद्योग क्षेत्रमें विदेशी बीमा कम्पनी को परवानगी के साथ ही वित्तीय एंव बँकिग क्षेत्र में मूलभूत

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

रचनात्मक बदल; सभी प्रकार की सहायता में कपात; उत्पन्न कर, कॉरपोरेट कर आदि सभी प्रत्यक्ष कर में कपात; तथा गैर एंव विश्वव्यापार संगठन के विधिनूसार भारतीय अर्थव्यवथा का जागतिक अर्थव्यवस्था में बढ़ता सम्मिलीकरण आदी मौलिक विशेषताए है|

इसी प्रभाव से भारतीय आर्थिक सुधार मुख्यत: कुछ मूलभूत विश्वासों पर आधारित है[६]| प्रथमता राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सरकार की मर्यादित भूमिका तथा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के विकास हेतू गति देनेवाले नीजी उद्योगो का प्राधान्य, अर्थात केंद्रिय नियोजीत अर्थव्यस्था का बाजारअर्थव्यवस्था में रुपांतरण करना आर्थिक सुधारणा का उद्देश्य है; द्वितीय आंतर-बाह्य प्रतिस्पर्धा से मर्यादित आर्थिक संसाधनो का सुयोग्य वितरण एंव उसके द्वारा अधिकतम कार्यक्षम प्रयोग, जिससे संसाधन के प्रत्येक घटकों द्वारा अधिक से अधिक लाभ मिलना लाभदायक होगा; तृतीय, अर्थव्यवस्था के साथ एकात्मिकरण की प्रवृत्ती से विदेशी पूंजी एंव तत्रंज्ञान से संचार उत्पादन क्षमता का विस्तार हो सकेगा, अन्त में आर्थिक वृध्दि के लाभ सिध्दात पर आर्थिक सुधार का विश्वास हैं|

उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है कि LPG की प्रक्रिया ने रोजगार की संधी कृषी के अन्तर्गत वास्तव मजदूरी के ऱ्हास अन्नधान्य खुरक्षितता को धोका; कल्याणकारी राज्य का ऱ्हास; दारिद्रयता में वृध्दि; आरक्षण नीतियों का संकीर्ण आदि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है. सार्वजनिक क्षेत्र का संकोच एंव निजि क्षेत्र का बढ़ता वर्चस्व के कारण रोजगार के क्षेत्र में कृषक मजदूरों, गरिब, दलित वंचितो को दिए गये मर्यादित संरक्षण भी संकट में आ गये है| सामाजिक परिप्रेक्ष्यमें एल पी जी (LPG) के नकारात्मक परिणाम से बचने हेतू कुछ प्रावधान या नीतिया [७]| को अमल में लाना उपयुक्त होगा| मौलिक प्रावधानों में विशेषता भूमिहिन परिवारों में सरकार द्वारा कृषीयोग्य जमीन का यथोचित वितरण तथा अन्य स्वयंसेवी संगठन के सहकार्य से सहकारी कृषी का प्रारंभ पायाभूत सुविधा की उपलब्धता करता संवैधानिक बांधीलकी के अनूरुप समूचित आरक्षण नीति को अंमल करना चाहिए; निजी क्षेत्रमें भी आरक्षण का प्रावधान होना, प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण विकास , रस्ते रोजगार निर्माण योजना तथा निवास आदि महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा पर व्यय बढ़ाना; केंद्र शासन द्वारा कृषी व ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बँक के अनूरुप कृषी मजदूरो संबंधी विकास बँक की प्रस्थापना, सरकार द्वारा कृषी मजदूर गरिब वंचितो के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना का सुत्रपात करना तथा किमान वेतन कानून को अंमल मे लाना; अंतं मे परिवर्तनशील परिस्थितियों में उचित शिक्षा कृषी मजदूरो को आर्थिक हक्क प्राप्त करने वाला अद्वितीय, योग्य तथा प्रभावी साधन है यही निर्वीवाद सत्य है .

सदर्भ :

१. वसु, दुर्गादास, " भारत का संविधान एक परिचय", वाघवा प्रकाशन, नागपूर, २००८ पृ.स. ३४७|
२. बैसंती, डी.के., "अम्बेडकर : दि टोटल रिवॉल्यूशनरी", सेजमेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यु दिल्ली, १९९१, पृ.स. ५८|
३. ग्रोवर, विरेन्द्र (संपादित), " भीमराव रामजी अम्बेडकर, ए बायोग्रॉफी ऑफ हिज व्हिजन एण्ड आयडियाज", दिप एण्ड दिप एपक्लिकेशन, न्यु दिल्ली, १९९८ पृ.स. ४६४|
४. सवरैया, जी एण्ड देवराजूलू एम , "इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ डॉ बी आर अम्बेडकर - रिलेव्हन्स टू द प्रेझेन्ट न्यू "इकोनॉमिक्स पॉलिसी", ठाकूर अनिलकुमार एंव दलीप कुमार (संपादित)'इकॉनामिक्स थॉटस ऑन जस्टिस एण्ड इक्वालिटी', दिप अण्ड दिप पब्लिकेशन, २००७, न्यु दिल्ली, पृ.स २४९- २५०|
५. जाटव, डि आर, "दी. प्राईम मुव्हर", ए.बी.डी.पब्लिशर्स जयपूर २००४ पृ.स.१२५ |
६. मुणगेकर डॉ भालचंद्र, "भारतातील आर्थिक सुधारणा आणि दलित एक आंबेडकरी दृष्टिकोन", सुगावा प्रकाशन पुणे, मार्च २०१२, पृ.स. ३६|
७. वही पृ.स. ५१-५२ |